



विश्व की अदभुत वस्तु हैरिटेज साइट्स में से एक है बुरकीना फासो के प्राचीन फेरस मेटलर्जि अवशेष। अफ्रीका के इस क्षेत्र में धातु का काम बेहद आम है तथा ईसापूर्व सन 800 से हो रहा है। लौह उत्पादन बुरकीना फासो की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग था। आश्चर्य यह है कि इन लोगों ने 2800 साल पहले मेटलवर्क के लिए आवश्यक औजार व भवन बना लिए थे। आयर्न मेटलवर्क के लिए मुख्यतया लोहे का खनन तो होता ही था, साथ ही, कभी-कभी सोना और मार्बल भी मिल जाता था, जिसका उपयोग ये लोग आभूषण और हथियार आदि बनाने के लिए करते थे। बुरकीना फासो की मेटलर्जी साइट्स पर भी खूबसूरत वस्तुओं को अफ्रीका के आसपास के भागों में बेहद कीमती माना जाता था, क्योंकि अन्य स्थानों पर ना तो कच्चा माल उपलब्ध था ना ही उसके संवर्धन की टेक्नॉलजी थी। बुरकीना फासो के पांच शहरों में पांच मेटलवर्किंग कॉम्प्लेक्स थे। पन्द्रह स्थानों पर इनके जो अवशेष मिले हैं उनमें प्राकृतिक नैचुरल ड्राफ्ट फरनेस (भट्टियाँ) हैं, जो लौह उत्पाद के लिए आवश्यक होते हैं। इन प्राकृतिक ड्राफ्ट फरनेस का उपयोग कच्चा लोहा पिघलाने के लिए और फिर लौह अयस्क से अशुद्धियाँ हटाने के लिए होता था। सबसे पुरानी भट्टी दौरीला में मिली है, जो संभवतया 800 ईसापूर्व की है। माना जाता है कि, सबसे पहले लोहा निकालने की शुरुआत यहीं हुई थी। एक अन्य शहर, बैक्वे में जो फरनेस मिले हैं, वे 500 ईसापूर्व के हैं। इनमें से अधिकांश आंशिक रूप से भूमिगत हैं। अन्य तीन जगहों पर भी फरनेस मिले हैं पर ये दसवीं सदी ईस्वी और उसके बाद के हैं। बड़े फरनेस पांच शहरों में ही हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में छोटे-छोटे फरनेस हैं। इसका अर्थ है कि लौह अयस्क को पिघलाना, साफ करना, प्राचीन बुरकीना फासो की जीवन शैली और परम्परा का अंग था, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित किया गया। आज भी मेटलर्जी बुरकीना फासो की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। यहां की प्राचीन फेरस मेटलर्जी साइट्स को वर्ष 2019 में युनेस्को ने वर्ल्ड हैरिटेज साइट घोषित किया था।

अमेरिका हर माह एक लाख भारतीयों को वीजा देगा

नई दिल्ली, 10 नवंबर (वार्ता)। कोविड महामारी के बाद तेजी से सामान्य हो रही परिस्थितियों के बाद अमेरिका ने भारत के लिए वीजा आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष इंतजाम किये हैं और आशा जतायी है कि अगले वर्ष गर्मियों तक भारत चीन को पछाड़ कर दूसरा सर्वाधिक अमेरिकी वीजा पाने वाला देश बन जाएगा। इस बीच खुशी की बात यह है कि, अमेरिका ने घोषणा की है कि, हर महीने एक लाख भारतीयों को अमेरिकी वीसा जारी किये जायेंगे।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यहां कहा कि अमेरिका की सरकार के लिए भारत नंबर एक प्रार्थमिकता वाला देश है। हम नवंबर मध्य में वीजा स्लॉट खोलने जा रहे हैं और अगले वर्ष 2023 में अमेरिकी मिशन अधिक वीजा आवेदनों का न्यूनतम संभव समय में निस्तारण कर रहा होगा। इसके लिए हम स्थायी एवं अस्थायी कार्डसलरों की भर्ती करेंगे और डॉपॉबॉक्स केंसों की संख्या भी

■ इस घोषणा के बाद, चीन को पीछे छोड़कर भारत सबसे ज्यादा अमेरिकी वीजा प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन जायेगा।

बढ़ाएंगे।अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने कुशल एवं तकनीकी कामगारों के लिए एच श्रेणी और प्रबंधकीय वर्ग के लिए एक श्रेणी के वीजा के लिए एक लाख नये स्लॉट खोल दिये हैं। हमें आशा है कि भारत अगले वर्ष गर्मियों तक अमेरिकी वीसा पाने वाले देशों की श्रृंखला में चीन को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी वीजा हासिल करने के मामले में भारत, मैक्सिको के बाद नंबर दो देश हो जाएगा।

एक साल के जवाब में उन्होंने बताया कि भारत को अगले वर्ष कोविड पूर्व की स्थिति की तुलना में कम से कम दोस फीसदी अधिक वीजा जारी किये जाएंगे।

संजय राउत के तेवर नरम पड़ गये हैं?

मुंबई, 10 नवम्बर पातरा चॉल स्कैम में 101 दिनों की जेल के बाद बेल पर बाहर निकले संजय राउत के तेवर अब क्या नरम पड़ गए हैं? उनके एक बयान से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। जेल से निकलने के बाद संजय राउत ने अब भाजपा से रिश्ते बदलने के संकेत दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा

■ संजय राउत ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनको अपने मामले की पूरी सच्चाई बताऊंगा।

कि मैं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करूंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं मोदी और शाह से मिलकर बताऊंगा कि क्या हुआ है और पूरा मामला क्या था। संजय राउत बुधवार शाम को ही जेल से बाहर आए हैं और सबसे पहले उड़व ठाकरे ने उनसे मुलाकात की।

ओ.बी.सी. आरक्षण मामले को लेकर हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रैफर होने पर काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर निशाना साधा

जयपुर, 10 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में ओबीसी वर्ग के पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण को ओबीसी कोटा में ही शामिल किया जाता है, जिसे लेकर विरोध चल रहा है। इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को उम्मीद थी कि वसुंधरा सरकार के समय लिए गए एक निर्णय को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को हुई कैबिनेट में बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले के स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेताओं में आपसी बयानबाजी शुरू हो गई है।

ओबीसी आरक्षण को लेकर विधायक हरीश चौधरी ने खुद को ही सरकार पर नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। हरीश चौधरी की नाराजगी की वजह है राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही विसंगति

■ खाचरियावास बोले, मेरा नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है।

पर कोई विचार नहीं हुआ।

इतना ही नहीं इस बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से किए गए विरोध की बातों भी सामने आई हैं, जिसे लेकर भी हरीश चौधरी ने नाराजगी जताई है।

हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को लेकर उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह सही नहीं है और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। कहा जा रहा है कि ओबीसी

आरक्षण में चल रही विसंगति को दूर करने को लेकर राजस्थान कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया।

जबकि पूरी उम्मीद थी कि मामला उठाया जाएगा। जब पूरी उम्मीदों के बाद भी ओबीसी आरक्षण की विसंगति को बुधवार रात हुई कैबिनेट मीटिंग में दुरुस्त नहीं किया गया और इस मामले को डेफर किया गया तो पूर्व मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी मुखरित हो गए।

उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए टिवटर पर लिखा कि कल कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था, कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौकाने वाला है। हरीश चौधरी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि “मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं

स्वस्थ हूँ। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ूंगा।”

बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण में चल रही विसंगतियों को लेकर मामला बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट में उठा था, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर अपनी बात रखते हुए इस पर और ज्यादा सोचने की बात कही। ऐसे में एक कैबिनेट के सदस्य की ओर से रखी बात के बाद प्रस्ताव को स्थगित किया गया। इस मामले को लेकर हुए विरोध में हरीश चौधरी ने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऐसे में हरीश चौधरी ने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य बिना नाम लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को निशाने पर लिया है।

प्रियंका की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का नेतृत्व किया है। राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सृजित वातावरण के विपरीत, इस पर्वतीय प्रदेश की चुनावी लड़ाई हर तरह से बहुत जबरदस्त रही है क्योंकि कांग्रेस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदा भाजपा सरकार को एक गम्भीर चुनौती देने में समर्थ रही है। प्रियंका गांधी ने स्थानीय मुद्दों को बखूबी उठाया और भाजपा को कड़ी चुनौती दी।

यह पहला अवसर था, जब पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी दोनों में से किसी ने भी हिमाचल में प्रचार नहीं किया। तथा प्रचार का सारा दायित्व को प्रियंका ने ही संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री बीरभद्र सिंह, जिनका गत वर्ष निधन हो गया था, को कमी जमीनी स्तर पर महसूस हुई क्योंकि राज्य में ऐसा कोई कांग्रेस नेता नहीं है, जिसका असर पूरे राज्य में हो।

चूँकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के कई दावेदार हैं, इसलिए पार्टी के विभिन्न प्रतिद्वंद्वी गुटों को संभालने की जिम्मेदारी इस युवा पार्टी महासचिव के कंधों पर ही थी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने परम्परा विरोधी गुटों को बखूबी संभाला है। अगर हिमाचल की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस की जीत हो जाती है तो प्रियंका पार्टी के एक उज्ज्वल सितारे के रूप में चमकेंगी तथा अगर भाजपा मतदाताओं की सत्ता-विरोधी प्रवृत्ति को पछाड़ कर, सत्ता में वापस आती है तथा प्रियंका के राजनैतिक भविष्य पर एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा।

दुष्कर्मी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में पीड़िता ने 11 जुलाई 2020 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अभियुक्त पर 19 अक्टूबर 2019 से 11 जुलाई 2020 तक दुष्कर्मी करने और डरा धमका कर डेढ़ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने जिरह में कहा कि उसने सहमति से संबंध बनाए। लेकिन अदालत ने पीड़िता के नाबालिग होने के चलते सहमति से बने संबंधों को भी दुष्कर्मी की श्रेणी में माना और अभियुक्त को सजा सुनाई।

गुजरात में भाजपा ने 38 मौजूदा मंत्रियों एवं विधायकों के टिकट काटे

भाजपा ने अभी 182 में से 160 उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है। पार्टी ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया है

अहमदाबाद, 10 नवम्बर। गुजरात भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने कहा कि पार्टी ने अपने तीन दर्जन से अधिक मौजूदा विधायकों और कई दिग्गज नेताओं को आगामी चुनावी मुकाबले से बाहर करने के साथ अपनी गुजरात इकाई में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत की है।

भाजपा ने गुरुवार को कुल 182 उम्मीदवारों में से 160 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में लगातार सातवें कार्यकाल पर नजर रखते हुए, पार्टी ने 38 मौजूदा

■ भाजपा ने मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा सोलंकी को जामनगर सीट से मैदान में उतारा है।

विधायकों को गिरा दिया, जिनमें से कुछ ने स्वेच्छा से घोषणा की कि वे 1 और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आये हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया है तथा मशहूर क्रिकेटर

रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा सोलंकी को भी जामनगर से मैदान में उतारा है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने बताया कि, अद्वितीय विधायकों को बदल दिया गया है। भाजपा आमदार पर अपने 20 प्रतिशत विधायकों को बदल देती है। चुनावी लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक है, अन्यथा यह गतिरोध को जन्म देगा। हमने कई युवाओं को टिकट दिया है। यह सूची एक पीढ़ीगत बदलाव दिखाती है।

पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा, प्रदीप सिंह

जड़ेजा और कुछ अन्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी लड़ाई से खुद को वापस ले लिया है। यह पूछे जाने पर कि ये वरिष्ठ नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इस पर पाटिल ने कहा, “उन्होंने स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इन सभी ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए अब वे संगठन के लिए काम करना चाहते हैं।

पार्टी ने आज जारी प्रत्याशियों की पहली सूची में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे युवा नेता हार्दिक पटेल को वीरमगम सीट से उतारा है।

उन्होंने कहा कि कन्या कुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा बहुत जरूरी हो गई थी क्योंकि मुख्याधारा का अधिकांश मीडिया कांग्रेस की पहलों को कवर ही नहीं करता। जब भीड़ ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसी ई.डी. के कथित दुरुपयोग का उल्लेख किया,

तो उन्होंने कहा, “हम इसी ई.डी. शी-डी से डरने वाले नहीं हैं। दो दिन पहले, 2016 में ज्यादा मूल्य वाले नोटों की नोटबन्दी की छठी वर्षगांठ पर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऐसा (नोटबन्दी) करके “एक आर्थिक सुनामी खुली छोड़ दी थी।

बुधवार रात को नांदेड़ में हुई एक मीटिंग में, गांधी ने कहा कि टाटा-एयर बस मिलिट्री एयरक्राफ्ट नेव्चर तथा वेदाना-फॉक्सकॉन सेमीकन्डक्टर प्लान्ट जैसे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से हटाकर, गुजरात को दे दिये गये क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं।”

ये प्रोजेक्ट उन दो-तीन उद्योगपतियों को दे दिये जायेंगे, जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं तथा देश का पैसा उनके हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। बन्दरगाह, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, कृषि क्षेत्र इन लोगों को दिये जा चुके हैं।

उन्का सर्वनाश हो रहा है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है तथा वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे पर कटाक्ष एवं प्रहार कर रहे हैं।

खाचरियावास और महेश जोशी एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर चला रहे हैं। स्थिति के और भी खराब होने की सम्भावना है क्योंकि गहलोत कमजोर होते जा रहे हैं तथा अपनी सरकार को एकजुट बनाये रखने में असमर्थ हो गये हैं तथा वे खासतौर से, अपने अस्तित्व को सुनिश्चित रखने पर फोकस कर रहे हैं।

सुन्दरेशन, ऑकलैण्ड सिटी कार्डिनल के लिए जानानी रामचन्द्रन, सॉल्ट लेक काउन्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए सिम गिल और वॉशिंगटन स्टेट सीनेट के लिए मानका धोंगडा।

इण्डियन-अमेरिकन उम्मीदवार कई ऐसे कड़े चुनावी मुकाबलों में फंसे, जिनमें से कईयों की जीत हो सकती है। इनमें हैं- मिशिगन स्टेट सीनेट के लिए पद्मा कम्पा, न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट के लिए जेरेमी कूनी, पैन्सिल्वेनिया स्टेट हाउस के लिए अन्ना थॉमस, फोर्ट बैंड काउन्टी जज के लिए जूली मैथ्यू, फोर्ट बैंड काउन्टी जज के लिए सुरेन्द्रन पत्तला और इस बार टैक्सस सिटी कार्डिनल के लिए खड़े हुए जोहेब क्रदरी।

चुनावी दौड़ में अन्य इण्डियन अमेरिकन भी हैं- जैसे एरिज़ोना स्टेट सीनेट के लिए प्रिया

फ़ारूख मुगल, मैरीलैण्ड में कुमार भवें और ओहायो में अनिता समानी। के.पी. जॉर्ज टैक्सस कोर्ट बैंड काउन्टी जज के पद पर, मोनिया सिंह टैक्सस हैरिस काउन्टी जज और अजय रमन ऑकलैण्ड काउन्टी कमिश्नर के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं।

इण्डियन-अमेरिकन उम्मीदवार कई ऐसे कड़े चुनावी मुकाबलों में फंसे, जिनमें से कईयों की जीत हो सकती है। इनमें हैं- मिशिगन स्टेट सीनेट के लिए पद्मा कम्पा, न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट के लिए जेरेमी कूनी, पैन्सिल्वेनिया स्टेट हाउस के लिए अन्ना थॉमस, फोर्ट बैंड काउन्टी जज के लिए जूली मैथ्यू, फोर्ट बैंड काउन्टी जज के लिए सुरेन्द्रन पत्तला और इस बार टैक्सस सिटी कार्डिनल के लिए खड़े हुए जोहेब क्रदरी।

चुनावी दौड़ में अन्य इण्डियन अमेरिकन भी हैं- जैसे एरिज़ोना स्टेट सीनेट के लिए प्रिया

मानते हुए उन्हें महापौर पद से बर्खास्त कर दिया था। साथ ही 6 साल के लिए निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किये थे।

सौम्या को बर्खास्तगी के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर शील धामाई को कार्यवाहक महापौर बनाया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पिछले दिनों चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके चलते भाजपा ने रश्मि सैनी को और कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को मेयर उम्मीदवार बनाया। करीब एक हफ्ते की बाढ़ेबंदी के बाद गुरुवार को मतदान हुआ। हेमा का दावा था कि उनके साथ कांग्रेस के 49 और 5 निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा से असंतुष्ट पार्षद भी उनके साथ हैं। जबकि, रश्मि अपनी पार्टी के 85 पार्षद एकजुट होने के दावे के साथ जीत तय मान रही थी। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने क्रॉस वोटिंग की संभावना को देखते हुए अपने-अपने प्रत्याशियों को बाढ़ेबंदी में कैद कर रखा था।

उधर गुरुवार को दोपहर ग्रेटर निगम के मेयर के चुनाव के लिए 146 पार्षद वोटिंग कर चुके थे। कार्डिंग चल रही थी, लेकिन रिजल्ट से ठीक पहले चुनाव प्रक्रिया को रोक गई। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अदालती आदेश से हालात ऐसे पैदा हो गए कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव प्रक्रिया रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ हुई न्यायिक जांच में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए सरकार से आधे घंटे में नया आदेश मांगा था। हालांकि सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने कोई नया आदेश पेश नहीं किया। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि सौम्या गुर्जर को सुनवाई का पूरा मौका मिले।

माना जा रहा है कि सरकार के अगले एक्शन तक सौम्या मेयर सकती है। सरकार अब नोटिस देकर सौम्या का पक्ष सुनने के बाद सस्पेंड कर सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में अभी के हालात में सौम्या गुर्जर पुनः मेयर का पद संभाल सकती हैं।

कौन से मुद्दे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भविष्यवाणी की है इस प्रकार की है। इंडिया टी.वी.-मैट्राइज ओपिनियन पोल्स के अनुसार, भाजपा को 46 प्रतिशत वोट तथा कांग्रेस को 42 प्रतिशत वोट मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सर्वेक्षण अरविन्द केजरीवाल की “आप” की अच्छी सम्भावनाएं नहीं बता रहे हैं। सर्वेक्षण भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप को राज्य में 2 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिलेंगे। हाल ही के वर्षों में, भाजपा ने राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल हैं, में हर पाँच साल पर सरकार बदलने की “रिवॉल्यूिंग डोर” प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। भाजपा रणनीतिकारों ने हिमाचल में प्रचार के दौरान महिला मतदाताओं तक पहुँचने पर जोर दिया है तथा भाजपा का सोच था कि महिला मतदाता हर पाँच साल पर सरकार को बदलने वाली प्रवृत्ति को उलटने में भावना पार्टी की मदद करेंगी। बुधवार को काँगड़ा तथा हमीरपुर में जनसभाओं को सम्बोधित करते हुये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुये कहा था कि हिमाचल की महिलाओं ने तय कर लिया है कि वे हर पाँच साल बाद सरकार को बदलने के रिवाज को बदल देंगी। “इसलिये, अब इसे कोई चीज नहीं रोक सकती।”

पाली के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के कई नोटिस देने के बाद भी धन जमा नहीं कवाया गया। कोर्ट की स्टे कॉपी देख ट्रांसपैरेंट नगर थाना विरुम सिंह साँद अपनी टीम के साथ वापस लौट गए, लेकिन बैंक की टीम दो घंटे तक वहीं रही। बैंक के वकील का दावा है कि दो कम्प्रे सीज कर दिए गए हैं। मकान पर बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, लीगल मैनेजर, जोनल मैनेजर व बैंक स्टाफ समेत पूरी टीम पुलिस जाबका के साथ पहुंची थी।

बैंक की टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे उदयपुर के एडवोकेट हनुमंत सिंह ने बताया कि बैंक ने सुरक्षा के लिए 2 गाँव बैठा दिए हैं। उन्होंने बताया कि सीआई ने ऑकलन रिपोर्ट फिर से करने का हवाला देकर सीज की कार्रवाई रुकवा दी।

थाना प्रभारी बोले कि इससे पहले 2019 में भी बैंक टीम मकान सीज करने पहुंची थी। उस समय पाली जिला मजिस्ट्रेट ने स्टे दिया था, जिस समय कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। इस मामले में सीआई विरुम सिंह साँद का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट ने स्टे रद्द करे हैं।